

मुख्य समाचार

- प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज अंतिम बैठक— ठेकेदारों की देनदारियों में देरी, भर्ती प्रक्रिया और हिमकेयर जैसे मुद्दों पर तप सकता है सदन।
- शिमला ज़िला के सुनी क्षेत्र में 15 दिसम्बर से कोलडैम प्रबंधन सोनार तकनीक से करवायेगा सिल्ट सर्वेक्षण—
- सर्वोच्च न्यायालय ने कई राज्यों में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में लगे बीएलओ पर कार्यभार कम करने के निर्देश किए जारी।
- प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट के चलते ठण्ड में लगातार इजाफा— साफ मौसम के चलते मनाली रोहतांग सड़क पर 10 दिसम्बर तक वाहनों की आवाजाही फिर शुरू।

विधानसभा सत्र

प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज अंतिम बैठक होगी। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें ठेकेदारों की पेमेंट में देरी, भर्ती प्रक्रिया, संस्थानों को बंद करने, हिमकेयर योजना, आबकारी नीति सहित कई अहम मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा गया है। नियम 62 के तहत दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में चर्चा के लिए लाए जाएंगे।

शीतकालीन सत्र के सात दिन काफी हंगामेदार रहे हैं। विपक्षी दल भाजपा ने जहां सदन के भीतर कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास किया वहीं बीजेपी रोज सदन के बाहर भी सरकार के 3 साल के कार्यों को लेकर बड़ी रैली कर हमला बोला। सरकार के व्यवस्था परिवर्तन के नारे को हिमाचल में व्यवस्था पतन बताते हुए 2027 में सरकार को बदलने का कार्यकर्ताओं में जोश भरा। सत्र के अंतिम दिन भी आज सदन का माहौल गरम रहने के आसार है। ठेकेदारों की देनदारियों सहित, संस्थानों को बंद करने, भर्ती प्रक्रिया और हिमकेयर योजना जैसे मुद्दे प्रमुखता से गूंज सकते हैं।

सिकंदर कुमार

केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार खिलाड़ियों द्वारा डोपिंग व मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए डोप रोधी कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा संसद में इस संबंध में उठाए गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। मनसुख मांडविया ने बताया कि डोप रोधी कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश में चलाए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2024 में 7 हजार 7 सौ 74 कि तुलना में इस वर्ष 7 हजार 7 सौ 51 नियंत्रण परीक्षण करने की योजना है।

सतलुज नदी

शिमला ज़िला के सुनी क्षेत्र में सतलुज नदी में बढ़ते जलस्तर और गाद के मामले को लेकर उपायुक्त अनुपम कश्यप ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने कहा कि सुनी क्षेत्र में कोलडैम प्रबंधन की ओर से सिल्ट के ऊपर सोनार सर्वेक्षण करवाया जा रहा है जो 15 दिसम्बर से शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 दिनों में सर्वेक्षण कार्य पूरा होगा, जिसके आधार पर सुनी क्षेत्र में भविष्य के लिए रणनीति बनाई जाएगी।

वहीं प्रभावितों का कहना है कि बरसात के समय सतलुज नदी में अधिक गाद आने से पानी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने समय रहते प्रशासन से सोनार सर्वेक्षण और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है।

गौरतलब है कि सोनार सर्वे एक ऐसी तकनीक है जो ध्वनि तरंगों का उपयोग कर पानी के नीचे वस्तुओं का पता लगाने, मानचित्रण करने और सर्वेक्षण करने के लिए की जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने कई राज्यों में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान में लगे बूथ स्तरीय अधिकारियों— बीएलओ पर कार्यभार कम करने के लिए कई निर्देश जारी किए। शीर्ष न्यायालय ने राज्य सरकारों को उनके काम के घंटों को अनुपातिक रूप से कम करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती पर विचार करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि राज्य सरकारों और राज्य चुनाव आयोगों द्वारा तैनात कर्मचारी ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए जब भी बीएलओ को कठिनाइयों का सामना करना पड़े, राज्य सरकारों को हस्तक्षेप करना चाहिए। न्यायालय इस संबंध की एकयाचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह समय बद्ध तरीके से कर्तव्य का पालन नहीं करने वाले बीएलओ के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई न करे।

संजौली मस्जिद मामला

शिमला की बहुचर्चित संजौली अवैध मस्जिद मामले में वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी को प्रदेश उच्च न्यायालय का बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने नगर निगम शिमला कमिशनर की अदालत के 5 अक्टूबर 2024 के फैसले को बरकरार रखते हुए मस्जिद की दूसरी, तीसरी व चौथी मंजिल गिराने के आदेश दिए हैं जिसको खुद वक्फ बोर्ड ने भी अवैध माना है और याचिका कर्ता ने न्यायालय में अंडरटेकिंग भी दी है न्यायालय ने चार सप्ताह में नगर निगम से भी जवाब मांगा है। धरातल व पहली मंजिल को लेकर मामले की सुनवाई 9 मार्च को होगी।

आग

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कोतवाली बाजार धर्मशाला स्थित होटल धौलाधार में देर सांय आग लगने की एक घटना में होटल में रखा किमती सामान जलकर राख हो गया। गनिमत ये रही कि इस अग्निकांड में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। होटल के कर्मचारियों ने सतर्कता बरतते हुए पर्यटकों समेत अन्य लोगों को भी बाहर निकाला। एच.पी.टी.डी.सी. के ए.जी.एम. ने इस घटना में करोड़ों रुपये के नुकसान की बात कही है। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आकांक्षी ज़िला चंबा को भरपूर लाभ मिल रहा है। ज़िले में इस रबी मौसम के लिए गेहूँ व जौ की फसलों का बीमा करने की प्रक्रिया इन दिनों जारी है।

मौसम

प्रदेश के चंबा, लाहौल स्पिति व किन्नौर ज़िले में आज बादल छाए हुए हैं हालांकि राजधानी शिमला सहित अन्य मैदानी इलाकों में आज दिन की शुरुआत धूप के साथ हुई है। पिछले कई दिनों से तापमान में लगातार आ रही गिरावट से लोगों को शुष्क ठंड का सामना करना पड़ रहा है। चंबा ज़िला में सर्दियों के मौसम के दौरान किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इधर, साफ मौसम के चलते मनाली से रोहतांग सड़क पर आगामी 10 दिसंबर तक के लिए वाहनों की आवाजाही फिर शुरू कर दी गई है। इस सड़क के खुल जाने से देश-विदेश से आए पर्यटकों को रोहतांग दर्रे पर पड़ी बर्फ व प्राकृतिक सुंदरता के दीदार का अवसर एक बार फिर मिलेगा।

और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से

आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग-अलग खबरों को प्रमुखता दी है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ब्यान पर अमर उजाला की सुर्खी है— आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ऊना, राज्य सूचना आयोग धर्मशाला होगा शिफ्ट। जबकि दैनिक जागरण का शीर्षक है—किसी को लाभ या दंड नहीं, शिमला की भीड़ को कम करना प्रदेश सरकार का लक्ष्य। दैनिक भास्कर के शब्द हैं— धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में भाजपा के कार्यकर्ता जुटे, सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया।

“अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर”

- प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज अंतिम बैठक— ठेकेदारों की देनदारियों में देरी, भर्ती प्रक्रिया और हिमकेयर जैसे मुद्दों पर तप सकता है सदन।
- शिमला ज़िला के सुनी क्षेत्र में 15 दिसम्बर से कोलडैम प्रबंधन सोनार तकनीक से करवायेगा सिल्ट सर्वेक्षण—
- सर्वोच्च न्यायालय ने कई राज्यों में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में लगे बीएलओ पर कार्यभार कम करने के निर्देश दिए जारी।
- प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट के चलते ठण्ड में लगातार इजाफा— साफ मौसम के चलते मनाली रोहतांग सड़क पर 10 दिसम्बर तक वाहनों की आवाजाही फिर शुरू।

=====